CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 29 ▫ अंक- 13 ▫ रायपुर, गुरुवार 5 फरवरी 2026 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

मंगल कार्बन प्लांट में ब्लास्ट : 9 माह के मासूम समेत 8 मजदूर झुलसे, सभी की हालत गंभीर

रायगढ़, 5 फरवरी (हाईवे चैनल)। जिले के खरसिया स्थित मंगल कार्बन प्लांट में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया. टायर रिसाइक्लिंग के दौरान बॉयलर में हुए जोरदार धमाके ने प्लांट परिसर को दहला दिया. इस दर्दनाक हादसे में 8 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनमें एक 9 महीने का मासूम बच्चा भी शामिल है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. यह पूरा मामला खरसिया थाना क्षेत्र के बानीपाथर का है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज दूर तक सुनी गई. टायर गलाने की प्रक्रिया के दौरान अचानक हुए इस ब्लास्ट से निकली गर्म गैस और आग ने आसपास काम कर रहे मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया. वहां मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक 8 लोग बुरी तरह झुलस चुके थे. हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, घायलों की स्थिति बेहद चिंताजनक है. कई मजदूर 70 से 80 प्रतिशत तक झुलस चुके हैं. विशेष रूप से 9 महीने के मासूम की स्थिति बेहद चिंताजनक है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, प्लांट में पुराने टायरों को गलाकर कार्बन बनाने (रिसाइक्लिंग) का काम चल रहा था. आशंका जताई जा रही है कि बॉयलर के भीतर दबाव अधिक बढ़ने या किसी तकनीकी खामी की वजह से यह विस्फोट हुआ. पुलिस और तकनीकी टीम इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि आखिर यह ब्लास्ट कैसे हुआ. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने प्लांट परिसर को सील कर दिया है और जांच शुरू कर दी है. सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्लांट में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था? खतरनाक रिसाइक्लिंग प्लांट परिसर के भीतर 9 माह का मासूम बच्चा कैसे मौजूद था? क्या मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे?मौके पर पहुंचे अधिकारियों का कहा कि जांच के बाद यदि प्लांट प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

हथियारों के साथ 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर

बीजापुर, 5 फरवरी (हाईवे चैनल)। जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियद नेल्लानार और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एक डीवीसीएम सहित कुल 12 सशस्त्र माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।

54 लाख रुपए घोषित था इनाम

आत्मसमर्पण करने वालों में 08 महिला माओवादी और 04 पुरुष माओवादी शामिल हैं। इन सभी माओवादियों पर कुल 54 लाख रुपये का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण के दौरान माओवादियों ने अपने साथ एक्ा्च-47 और दो स्क्र्राइफल भी पुलिस को सौंपे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले सभी 12 माओवादी फायरिंग, आईईडी ब्लास्ट, आगजनी सहित कई गंभीर नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं। यह आत्मसमर्पण बस्तर आईजी पी. सुंदरराज, सीआरपीएफ डीआईजी देवेंद्र सिंह नेगी, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूलेण्डन यार्क, डीएसपी शरद जायसवाल, उप पुलिस अधीक्षक विनीत साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत अधिकारियों ने प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये की नगद सहायता राशि प्रदान की।

मुठभेड़ में नक्सली कमांडर उधम सिंह के मारे जाने की खबर!

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पेद्दागेलूर जंगल क्षेत्र में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में खूंखार नक्सली कमांडर उधम सिंह के मारे जाने की खबर सामने आई है। डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौके से एक एके-47 राइफल और नक्सली का शव बरामद किया है। यह कार्रवाई बस्तर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के तहत एक बड़ी रणनीतिक जीत मानी जा रही है। कमांडर स्तर के नक्सली के मारे जाने से स्थानीय नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है, जिससे बीजापुर के अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। जानकारी के अनुसार, सुरक्षाबलों को पेद्दागेलूर के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सटीक सूचना मिली थी। इसके बाद छ्रत्र्र और कोबरा जवानों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी शुरू की। खुद को घिरता देख नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में जवानों ने भी मोर्चा संभाला। बताया गया कि मारे गए नक्सली की पहचान कमांडर उधम सिंह के रूप में हुई है। फायरिंग रुकने के बाद जब इलाके की सर्चिंग की गई, तो वहां से एक ऑटोमेटिक एके-47 राइफल और अन्य युद्ध सामग्री बरामद हुई।

सुरक्षा बलों ने बरामद किया नक्सलियों का डंप, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद

सुकमा, 5 फरवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले 'गढ़' गोगुंडा में सुरक्षाबलों का ऑपरेशन लगातार दूसरे दिन भी जारी है. आज गुरुवार को सीआरपीएफ 74वीं बटालियन और कोबरा 201 के जवानों ने एक संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों के हथियारों के डंप को बरामद कर उनकी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, सुरक्षाबल इलाके में सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन पर निकले थे. इसी दौरान गोगुंडा पहाड़ के दूसरे छोर पर जवानों को नक्सलियों द्वारा छिपाया गया हथियारों का एक बड़ा डंप मिला. तलाशी के दौरान वहां से 5 किलो वजनी एक शक्तिशाली बम भी बरामद किया गया. नक्सलियों ने यह बम जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाया था, जिसे बम निरोधक दस्ते ने सूझबूझ दिखाते हुए मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया.

ब्रेकिंग न्यूज

भारत में कब और कहां दिखेगा साल का पहला ब्लड मून..!

नई दिल्ली, 5 फरवरी (न्यूज चैनल)। साल 2026 की शुरुआत खगोल प्रेमियों और ज्योतिष में रुचि रखने वालों के लिए एक बेहद खास खगोलीय घटना के साथ होने जा रही है। 3 मार्च 2026 को साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, जो 'ब्लड मून' के रूप में दिखाई देगा। इस दौरान चंद्रमा लालिमा लिए नजर आएगा। यह दुर्लभ नजारा भारत के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा।

ब्लड मून एक विशेष खगोलीय घटना है, जो पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान दिखाई देती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं और पृथ्वी इनके बीच आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया पूरी तरह चंद्रमा पर पड़ती है। इस स्थिति में चंद्रमा पूरी तरह अंधकारमय नहीं होता, बल्कि लाल, तांबे या गहरे नारंगी रंग में चमकने लगता है। ऐसा पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने वाली सूर्य किरणों के कारण होता है। नीली रोशनी बिखर जाती है, जबकि लाल रंग की किरणें चंद्रमा तक पहुंचती हैं, जिससे वह लाल दिखाई देता है। इसी वजह से इसे ब्लड मून कहा जाता है। खगोलीय गणनाओं के अनुसार, साल 2026 का पहला ब्लड मून 3 मार्च 2026 को दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया 2 मार्च की देर रात से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक चलेगी। इस बार ब्लड मून का दृश्य भारत के अधिकांश हिस्सों में देखा जा सकेगा। पूर्वोत्तर भारत में यह दृश्य सबसे ज्यादा स्पष्ट रहेगा। असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, आइजोल, ईटानगर और कोलकाता जैसे शहरों में चंद्रमा का लाल रंग अधिक समय तक नजर आने की संभावना है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में चंद्र ग्रहण का आंशिक चरण देखा जा सकेगा।

यूरोपीय संघ और अमेरिका के बाद अब खाड़ी देश भारत से व्यापार समझौता करने को तैयार

नई दिल्ली, 5 फरवरी (न्यूज चैनल)। यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों में तेजी दिखाने के बाद अब खाड़ी देश भी भारत के साथ हाथ मिलाने को उत्सुक नजर आ रहे हैं। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों में भारत की बढ़ती साख, आत्मविश्वासी विदेश नीति और मजबूत होती आर्थिक ताकत की साफ गूंज है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब भारत को बाजार भर नहीं, बल्कि साझेदार शक्ति के रूप में देखने लगी हैं। हम आपको बता दें कि भारत और खाड़ी क्षेत्र के छह देशों के समूह खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में एक अहम कदम उठने जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में दोनों पक्ष वार्ता की रूपरेखा पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। यह रूपरेखा आने वाली बातचीत का दायरा, तरीका और प्राथमिकताएं तय करेगी। इस तरह लगभग दो दशक से अटकी प्रक्रिया अब फिर गति पकड़ती दिख रही है।

6 सहकारी समितियों के खातों से 10 करोड़ का गबन

रायगढ़, 5 फरवरी (हाईवे चैनल)। बरमकेला अपेक्स बैंक के 10 करोड़ रुपए के गबन के मामले की जांच अब ईओडब्ल्यू करेगी। इस मामले में समिति प्रबंधकों की भूमिका भी संदेहास्पद है। बैंक से जुड़े 6 सहकारी समितियों के खातों से 10 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। इसके बाद भी अब तक दर्ज एफआईआर में सिर्फ बैंक अधिकारी कर्मचारियों के नाम हैं।

ईओडब्ल्यू करेगी मामले की जांच

बरमकेला अपेक्स बैंक में वर्तमान में 6 सहकारी समितियां संचालित होती हैं। इन्हीं समितियों से जुड़े खातों के जरिए करीब 10 करोड़ रुपए की राशि निकाले जाने की बात सामने आई है। बैंकिंग नियमों के अनुसार समिति खातों से बड़ी राशि के लेन-देन में समिति प्रबंधक की जानकारी और दस्तावेज जरूरी होते हैं। इसके बावजूद अब तक की कार्रवाई में किसी भी समिति प्रबंधक का नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान शाखा प्रबंधक की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में तत्कालीन डीआर वाघमारे, लेखाधिकारी मीनाक्षी मांझी और लिपिक आशीष पटेल के निजी बैंक आईडी-पासवर्ड का उपयोग कर बड़ी संख्या में ट्रांजेक्शन किए गए। उनके अलावा बैंक के अन्य पांच कर्मचारी भी दोषी पाए गए हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर संजय कन्नौजे ने कहा कि मामले की जांच के लिए पहले ही एक विशेष टीम गठित की गई थी। फिलहाल वर्तमान स्थिति पर अभी कुछ कहना संभव नहीं है, इस संबंध में सहकारिता विभाग से जानकारी ली जा सकती है।

प्रदेश में खुलेंगे 4 नए उप पंजीयक कार्यालय

रायपुर, 5 फरवरी (हाईवे चैनल)। प्रदेश में आम नागरिकों को रजिस्ट्री एवं पंजीयन से जुड़ी सेवाएं सहज, सुलभ और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियमङ्क1908 के प्रावधानों के तहत भखारा (जिला धमतरी), लवन (तहसील मुख्यालय, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा), सकरी एवं राजकिशोर नगर (बिलासपुर) में चार नवीन उप पंजीयक कार्यालय खोलने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

भखारा, लवन, सकरी और राजकिशोर नगर में उप पंजीयक कार्यालयों को मिली स्वीकृति

प्राप्त जानकारी के अनुसार धमतरी जिला के भखारा में नवीन उप पंजीयक कार्यालय खोलने हेतु प्रशासकीय स्वीकृत दी गई है। इसी प्रकार जिला पंजीयक बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत तहसील मुख्यालय लवन और बिलासपुर जिले के राजकिशोर नगर एवं सकरी में उप पंजीयक कार्यालय खोलने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया गया है। इन नए उप पंजीयक कार्यालयों के खुलने से संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को रजिस्ट्री कार्य के लिए दूरस्थ जिला मुख्यालयों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और धन की बचत होगी, भीड़ कम होगी तथा पंजीयन प्रक्रिया अधिक सुगम और पारदर्शी बनेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और प्रशासनिक कार्यों में गति आने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि शासन की सेवाएं आम नागरिकों तक उनके निकटतम स्तर पर उपलब्ध हों। नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्वीकृति से लोगों को पंजीयन संबंधी कार्यों में बड़ी राहत मिलेगी। यह निर्णय सुशासन की दिशा में एक और सशक्त कदम है, जिससे नागरिकों का समय बचेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।

वित्त एवं वाणिज्य कर पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य हमारी सरकार नागरिक सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।चार नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्वीकृति इसी सोच का परिणाम है। नए उप पंजीयक कार्यालय खुलने से पंजीयन व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को उनके क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकेंगी, जिससे प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और त्वरित होगी। उन्होंने बताया कि पंजीयन विभाग द्वारा 10 नए क्रांतिकारी सुधार लागू किए गए हैं, जिनका लाभ इन क्षेत्रों के नागरिकों को भी मिलेगा। इनमें ऑटो डीड जनरेशन, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, घर बैठे रजिस्ट्री, स्वत: नामांतरण, ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाणपत्र, एकीकृत कैशलेस भुगतान, व्हाट्सएप आधारित सेवाएं, डिजीलॉकर एकीकरण, डिजी-डॉक सेवा तथा खसरा नंबर के माध्यम से ऑनलाइन सर्च एवं रजिस्ट्री डाउनलोड की सुविधा शामिल है। राज्य सरकार के इस निर्णय को जनहित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे पंजीयन व्यवस्था अधिक विकेंद्रीकृत और प्रभावी बन सकेगी।

तेंदुए का शावक खेत में कर रहा था विचरण, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, भेजा जा रहा जंगल सफारी

धमतरी, 5 फरवरी (हाईवे चैनल)। जिले क़े नगरी सिहावा क्षेत्र क़े जंगलो मे वन्य प्राणियों क़े विचरण कि खबरे आती रहती है. इस बार एक तेंदुए क़े शावक क़े विचरण कि घटना सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार मामला बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के छिपली पारा गांव की बताई जा रही है,जहां तेंदूए के करीब 5-6 माह का शावक, श्रृंगी ऋषि पहाड़ी के नीचे से चलकर वनक्षेत्र से राजस्व इलाके में पहुंच गया था,वहीं जब स्थानीय लोगों ने शावक को खेतों के बीच देखा तो हैरान रह गए,जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई।जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पहुंचकर शावक को लेकर वेटनरी अस्पताल नगरी पहुंचे जहां से जांच के बाद उसे जंगल सफारी नया रायपुर भेज दिया गया है,जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी की शावक का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेंद्र कुमार अजय ने बताया कि शावक करीब 5 से 6 माह का है, पानी में भीगा हुआ था.स्थिति सामान्य है,जंगल सफारी भेजा जा रहा है।

राज्यसभा : खरगे बोले- हम संसद बाधित करना नहीं चाहते; नाराज सभापति ने टोका- सच्चाई बयान करें, लोकतांत्रिक बनें

नई दिल्ली, 5 फरवरी (न्यूज चैनल)। संसद के बजट सत्र का आज सातवां दिन है। पीएम मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं। इससे पहले राज्यसभा में बोलते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल गांधी को लोकसभा में ना बोलने देने का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में खरगे ने कहा, %संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता देश के हितों पर बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। आप इस तरह से सदन कैसे चला सकते हैं? जिस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, %विपक्ष के नेता को पता होना चाहिए कि लोकसभा की कार्यवाही पर राज्यसभा में चर्चा नहीं की जा सकती।% उन्होंने आगे कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, %आज हम सभी उम्मीद करते हैं कि सभी सांसद सदन के नियमों और परंपराओं का पालन करेंगे।

चूहा- सुनती हो, बंगाल की सीएम ममता बेनर्जी एसआईआर पर अपना खुद पैरवी कर रही हैं।

चुहिया- हां जी, पता नहीं वकील कब क्या बोल देंगे।

25 मार्च से होगी स्कूलों में पहली से 11 तक की परीक्षाएं

रायपुर, 5 फरवरी (हाईवे चैनल)। प्रदेश के स्कूलों में सत्र 2025-26 की वार्षिक परीक्षा को लेकर कक्षा 1 से 11वीं तक के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश केअनुसार वार्षिक परीक्षाएं 25 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की समय-सारणी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से जारी की जाएगी। उपसंचालक लोक शिक्षण के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले में वार्षिक परीक्षा के सफल संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। इसके लिए जिला स्तर पर संचालन समिति, प्रश्न पत्र निर्माण समिति और मॉडरेशन समिति का गठन 5 फरवरी 2026 तक किया जाना अनिवार्य होगा।

निर्देशानुसार कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के लिए ब्लूप्रिंट के अनुरूप प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। परीक्षा पूर्व तैयारी के तहत सैंपल प्रश्न पत्र बनाकर विद्यार्थियों को अभ्यास कराया जाएगा। सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रम 28 फरवरी 2026 तक पूर्ण कर रिवीजन कराया जाएगा, वहीं परियोजना कार्य की वार्षिक परीक्षा 5 मार्च 2026 तक पूरी की जाएगी। प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया के तहत 15 फरवरी 2026 तक प्रश्न पत्रों के तीन सेट तैयार किए जाएंगे। इसके बाद 20 फरवरी 2026 तक मॉडरेशन प्रक्रिया पूरी होगी। प्रश्न पत्रों को मुद्रण के लिए 25 फरवरी 2026 तक भेजा जाएगा, जबकि मुद्रक द्वारा सीलबंद लिफाफों में प्रश्न पत्र 15 मार्च 2026 तक जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे जाएंगे। जारी निर्देश सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर लागू होंगे।

स्थानीय परीक्षाओं से निजी स्कूलों को किया गया अलग, शिक्षा विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश

रायपुर, 5 फरवरी (हाईवे चैनल)। शिक्षा विभाग द्वारा पिछले दिनों जारी एक आदेश के चलते निजी स्कूलों के बीच तहलका मच गया था। दरअसल छ्व्क्क्ष् ने अपने आदेश में उल्लेख किया था कि प्रदेश भर में संचालित समस्त निजी विद्यालयों की स्थानीय परीक्षाएं शिक्षा विभाग ही कराएगा। इसका निजी स्कूल संचालकों ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के आदेश पर विभाग ने नया संशोधित पत्र जारी किया है। नए आदेश के बाद अब निजी स्कूल पूर्व की तरह अपने स्कूलों में ही परीक्षाएं ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इसी के मद्देनजर शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया है।

CMYK